श्री मधु लिमये :

टेप बजाया जाया अगर वह करेक्ट करना चाहते है तो मैं विरोध नही करता हूं वह आप की इजाजत से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन को फैक्ट एडमिट तो करना चाहिये कि उन्हों ने मिस्टेक की।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने कहा था 1972 मे मैं था। जून 1970 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक में विदेश व्यापार मंत्री था। यह बात मैं ने उस दिन भी कही।

श्री मधु लिमये : फिर कहिये मेरी गलती हुई स्लिप आफ टंग हुआ उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ औबजरवेशन करेंगे हम भी करेक्ट करते हैं, लेकिन झूठ तो नही बोलगे यहां।

MR DEPUTY-SPEAKER: The Minister has said that in the Uncorrected Report it was mentioned as 'January 1972' but when his attention was drawn ...

SHRI MADHU LIMAYE: Even the word "January" is not there. I remember it is only "1970".

इन का इटेंशन देखिये चूकि जनवरी 197। की बात पहले आयी थी उन्हें ने जनवरी 1972 कहा। नही कहा। केवल 1972 कह।

MR DEPUTY-SPEAKER: You have made your point. Why don't you listen to me. The Minister has said very clearly that in the Uncorrected Report it was mentioned as 'January 1972".

SHRI MADHU LIMAYE. No You consult the uncorrected report.

MR DEPUTY-SPEAKER Let me tell you what he has said. Why are you getting annoyed? Here he says that in the Uncorrected report it was mentioned as 1972 but when his attention was drawn to it, he corrected it; he changed "1972" to "1970". That is what he said. Whenever we make speeches here there may be some slips of the tongue. But when we see in the report something that is not correct, it is the normal practice that we take the earliest opportunity to correct it, and he has done it. Therefore, there cannot be any intention of misleading the House.

16.19 hrs.

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up further consideration of the Reserve Bank of India (Amendment) Bill. Shri M. C. Daga was on his legs.

श्री मधु लिमये (बाका): इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मै जब शुक्रवार को रिजर्व बैंक बिल के बारे मे बोला तो मैंने डिपाजिट्स के बारे में कहा क्या पोजिशन है यह जानने की कोशिश की। बाद में लाइब्रेरी वालों ने रिजर्व बैंक से डाकूमेंट्स ला कर मुझे को दिये, जो वह पहले नहा दे सके क्योंकि दो किस्म के डोकूमेंट्स थे, उस से पता ही नही चलता कान सा आर्डर फोर्स मे है। मैने शनिवार को पत्र भेजा था रोस्ट से कि सोमवार दोपहर तक मुझे बता दीजिये कि क्या वह नीला कागज वाला इन फोर्स है या ब्रोचर वाला इन फोर्स है। रिजर्व बैंक वाले कोई भी इत्तिला हमे देने के लिए तैयार नही है। हम लोग क्या करें? हम बोलना नहा चाहते है। तब तक जब तक कि ऑथेंटिक इनफार्मेशन हमें मिल नही जाती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, you have made your point.

SHRI MADHU LIMAYE: You pass a stricture on the Reserve Bank Governor. He is trying to deliberately confuse by giving two brochures.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made the point. It is not a point of order. But, I think, the Deputy Minister will take note of it.

When she replies, I think, she will deal with it.

श्री मधु लिमये : सुशीला जी जवाब नहीं दे सकती हैं। मेरे पास सब मारुति का मालला पड़ा हुआ है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इस पर बोलते हुए मैंने बताया था कि कहां कहां रिजर्व बैंक फेल हुआ है और क्या क्या रिजर्व बैंक ने काम किया है। जो कुछ आपकी रिपोर्टस् कहती हैं वही मै आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो फेल्योर में बताने जा रहा हूं इससे ज्यादा और बड़ी फेल्योर क्या हो सकती है?

"Various field investigations provide instances of cooperatives continuing to be dominated by money lenders and others who use the funds of the societies to promote their own ends, financial and political."

इस प्रकार से आपका पैसा चला जाता है।

"There is a fairly widespread impression that vested interests have so established themselves in the management of primary agricultural credit societies that in many parts of the country, they are virtually monopolising the benefits of co-operative credit."

कोआपरेटिव सोसाइटीज और छोटे काश्तकारों के नाम ले कर आप बिल पेश करते हैं, एमेंडमेंट्स पेश करते हैं। इसको देख कर दुख होता है कि इस तरह से आपका पैसा वेस्ट होता है; कौन ले जाते हैं? बड़े-बड़े मनी लैण्डर्स वेस्टिड इटरेस्ट्स, एक एक फैमिली ले जाती है। उस पैसे की अब हालत क्या है? इसके बारे में क्या आपकी रिपोर्ट कहती है:

"The high level of overdues at the various levels of cooperative credit structure continues to plague the movement thereby choking the flow of credit. The competitive position of overdues for the years 1971-72 and 1972-73 at the level of the central cooperative banks and the primary societies was 44 per cent by the end of 1971-72. It was, however, as high as 80 per cent in Assam, 82 per cet in Manipur, 80 per cent in West Bengal, 63 per cent in Rajasthan, 62 per cent in Bihar and 57 per cent in Orissa."

अरबों रुपया इस तरह से लोगों की तरफ बकाया पड़ा हुआ है जोकि रिकवर नहीं हो पा रहा है। कहते तो यह हैं कि रूरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं लेकिन वेस्टिड इटरेस्ट। उनको आपने मदद दे रखी है। ये लोग जान बूझ कर वापिस करना नहीं चाहते है। आपकी गवर्नमेंट मशीनरी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। छोटे काश्तकारों तक लोन पहुंचता नहीं है।

आपने इसको क्लीयरली माना है

"The Survey Committee summing up the position in regard to agricultural credit observed that it fell short of the right quantity, was not of the right type, did not serve the right purpose and often failed to go to the right people and that 'co-operation had failed but co-operation must succeed'."

आप कहते है कि आप एनीमल हसबैंडरी के वास्ते लोन बढ़ा देंगे। लेकिन यहां माननीय सदस्य कह रहे है कि सीकर में शेड्यूलकास्ट और ट्राइबज के लोगों की कोई दो सौ एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दो सौ साल हो गए हैं लेकिन कुछ उन पर कारवाई नहीं की गई है। आप को इस सब के बारे में हमारे सामने रिपोर्ट रखनी चाहिये थी और हमको बताना चाहिए था कि इतने गरीब लोगों को आपने इतने लोन दिए है। आपका अरबों रुपया मालदार लोग खा गए है। हम नहीं यह आप खुद कह रहे ह जब ऐसी बात है तो रिजर्व बैंक का इस तरह की जो गड़बड़ीयां होती है इन पर क्या कन्ट्रोल है।

[श्री मूलचन्द डागा]

मैंने पिछली बार कहा था कि बडोदा के बैंक मैनेजर ने 45,000 रुपया उसको दिया जिस का जमाई या लडका या लड़की पार्टनर है कम्पनी मे।

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, if you go into all the details.

SHRI M. C. DAGA: I am not going into the details, I am simply touching the points.

MR. DEPUTY-SPEAKER: These are the details of what this bank has done or that bank has done. If you go into those details, there will be no end to it Confine yourself only to the main points of the Bill

SHRI M C. DAGA: After all, the Reserve Bank has to supervise and control.

MR DEPUTY-SPEAKER: I know As I said, if you start going into the details, there will be no end.

SHRI M C. DAGA: I am not going into the details, Sir They have got this provision in the Bill I am just pointing that out

रिजर्व बैंक की पालिसी है कि इडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन न दिए जाए। छोटे-छोटे उद्योगो को भी नही देगे। मे जानना चाहता हू कि आखिर इन लोगो को लोन मिलता ही कितना है? मै समझता हू कि लोन के मामले मे रिजर्व बैंक की कोई यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये।

बैंकों के नेशनलाइजेशन के वक्त पिछले वित्त मन्त्री ने बहुत सी बाते कही थी। लेकिन आज हालत क्या है? जहा 9 करोड रुपया ओवर टाइम का स्टाफ को दिया जाता था वहा 11 और 13 करोड दिया जाने लग गया है। स्टाफ वैसे ही बैंको मे ज्यादा है। हर साल यह बढता जाता है। हम लोग कई बार कह चुके है कि ओवर टाइम आप बन्द करे। लेकिन सारी गडबड़ी चल रही है। रिजर्व बैंक का कोई कन्ट्रोल नही है। सिविल सर्वेन्ट्स जिन को आप डायरेक्टर बना देते है रिजर्व बैंक के वे करते क्या है। आर्थिक सकट आ गया मुद्रा स्फीति हो गई। क्यो हो गई? क्या रिजर्व बैंक का कोईकाम नही था, उसकी कोई जिम्मेदारी नही थी।

The Deputy-Speaker has put restrictions on my speech. Otherwise, I could quote many things.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to put restrictions. Just as the banks are applying squeeze, I will have to apply squeeze on your time.

SHRI M. C. DAGA: I am pointing out because it concerns the Reserve Bank.

MR DEPUTY-SPEAKER: I am concerned with time and relevancy.

श्री मूल चन्द डागा क्या पालिसी लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की है समझ मै नही आत है। गरीब आदमी को पिछले 20 साल मे चार पाच रुपया पर कैपिटा भी नही मिला है, तीन रुपया भी नही मिल रहा है। मनी लैण्डर्स की तरफ अरबो रुपया बकाया पडा हुआ है। कौन रिकवर करगा? जो आपके बैंको वाले है वे जहा उनका इटरेस्ट इनवाल्व्ड होता है, वहा लोन देते है बडी बडी बिल्डिग बैंको की बन गई हैं। भत्ता टी, ए, डी, ए आदि बड गए है। हवाई जहाजा मे आते जाते है। चार लाख का फरनीचर ले कर रख लिया गया है बको मे यह सब आपकी रिपोर्ट्स कहती है।

आप क्लाज 25 में सेक्शन 58के बाद एक सेक्शन जोड़ना चाहते है.

"No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the Bank or any other person in respect of anything which is in good faith done...."

यह कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य बनने के बाद यह कौन्सा नया प्रिवलेज है? यह कौन सा तरीका है कि गवर्नमेंट आफिसर पर डिपेंड किया जाय और आप गवर्नमेंट आफिसर को दूसरे लेवेल पर रखते हैं और जो इंडिविजुअल सिटिजन है उस को दूसरे लेवेल पर रखते है? यह इस की क्या जरूरत पैदा हुई कि कोई बैंक मैनेजर कोई गलत करता है तो उस के लिए आप यह कह रहे हैं कि उस के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लाई जा सकतीं या कोर्ट में नहीं जा सकते और हम कोई गलती करें तो वर्डेन एक्यूज्ड पर लाद करता है। हमारे पर वर्डेन है कि हम अपनी इनोसेंस मूव करें। आप का ला कमीशन यह निर्णय देता है कि एकोनामिक आफेंसेज में वर्डेन उन पर शिफ्ट कर दो, दे हैव टु पुट दैट और आप यहां यह लिख रहे है कि अगर कोई बैंक एम्प्लाई या आफिसर कोई गलती करता है तो उसे यह माना जाय कि दे हैव डन इट इन गुड फेथ। मैं नहीं समझ पाता कि यह डिस्टिंक्शन कैसे पैदा हुआ कि कोई उन को प्राजीक्यूट कर ही नहीं सकता।

If any bank employee or officer does anything in good faith.....I have not understood good faith. Nobody can prosecute him.

Suppose the bank has served a notice on me to produce certain documents and I have lost the documents, you say, 'You have failed. I will prosecute you'. I say, 'Please give me a chance. I do not possess those documents'. He says, 'No. If you fail to produce the documents, you will be prosecuted.'

यह जो इस तरह के प्राविजन्स है कोर्ट में जाने नहीं देना चाहते और कोर्ट्स के राइट्स जहां जहां कर्टेल करना चाहते हैं तो आदमी अपने अधिकारों की रक्षा वहां कैसे करेगा? वह अपने को डिफेंड कैसे करेगा?

Now I am debarred from going to the court against any officer or bank employee. No prosecution, no case, no criminal case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Good faith is also justiciable.

SHRI M. C. DAGA: When we do it, we also do it in good faith.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना). उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the bell be rung....

Yes, now there is quorum, Shri Sequeira.

SHRI ERASMO de SEQUEIRA (Marmagoa): The Bill which is before us amends an Act which was passed in 1934. Many things have happened to the country since then. Many changes have taken place in the Reserve Bank and many a naya paisa has tumbled from the rupee. I am terribly sorry that the Government has failed to take this opportunity not merely to come forward with a small amending Bill, but to really examine the original Act and see whether it is suitable and whether any changes are required to make the Reserve Bank an effective instrument in the conditions of to-day.

I see in this Bill two things which are symptomatic of the malaise that is facing us to-day. The malaise, where for the sake of expediency we sacrifice principle. Here, in the new Section 18A you have a clause which says:

> "the validity of any loan or advance granted by the Bank in pursuance of the provisions of this Act shall not be called in question...."

merely for the reason that the Memo-

[Shri Erasmo de Sequeira]

randum or Articles of Association do not allow such a loan. You introduce here a very dangerous element; by law you are authorising a body to take a loan which is prohibited by its own articles of association. One principle is thrown to the winds. Then, in another section what you have done is this Section 24 of this Act says that any regulation made under this section shall have effect from such earlier or later date as may be specified in the rules. Therefore, you start with making regulations with retrospective effect And you throw another principle that underlines the rule of law to the winds.

This is what we see every day. The Supreme Court passes a judgment, it says something about expenditure The next day we have a proclamation which reverses the supreme court ruling Again in regard to MISA it is the job of the Courts under the Constitution to examine and pass verdict; the next day we find a Presidential Order taking this power away from the Courts This is sheer expediency, subverting the rule of law, and this sort of thing is happening constantly. One has fears that one is heading for a system of single party Government

MR. DEPUTY-SPEAKER Last time it was Pratipaksha; this time it is one party

SHRI MADHU LIMAYE which is edited by Mr George Fernandes

SHRI ERASMO de SEQUEIRA You have enlarged the definition of deposits to such an extent, that very soon, if you go into the inspection that this Bill provides for, you will have to add so many clerks to the Reserve Bank staff that it will become as Parkinsonian a delight as any other Ministry of the Government of India! If we believe in a free society and in a democracy, we must accept the fact that whichever Government is in power is only a transient having a tenure of 5-years. Beyond that it must go and get the support of the people. So far as basic things like currency and finance are concerned, we must permit institutions like the RBI to have the degree of independence to guarantee continuity which is very necessary. I was hearing a story from my colleague about....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't tell private stories

SHRI ERASMO de SEQUEIRA: It is not a private story.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : पांच पांच रुपये के और सौ सौ रुपये के नोट और इप्लिकेट नोट इस देश भर में फैले हुए है और यह मिनिस्टर भी जानते है।

SHRI DEPUTY-SPEAKER: If you don't keep confidence you may carry on.

SHRI ERASMO de SEQUEIRA: This was about the large number of duplicate five rupee and hundred rupee notes recently found in Allahabad. These are things one never heard of in the past These are things which are happening increasingly and more and more frequently. These are things which are happening when standards are lowered and these are things which get lowered by constant interference. The Reserve Bank is supposed to be an independent institution, it is supposd to advise Government independently. Today it is being denied that opportunity, and from this side of the House I would like to insist and demand that that independence has to be restored.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think to-day somehow some of the speakers who have just finished have preoccupied themselves with MISA with economic offences, with courts etc And therefore, in that background, I do not know how far they have really been very fair to the amendments which are before us

in this House. I am in no position to say whether they were relevant because, every Member is entitled to his opinion. But, I think, if it were regarding the budget, they may be in a position to say something. Anyway, I can understand the background with which what has been pointed out. On the whole, most of the Members have, by and large, welcomed the amendments. Of course they have disagreed on one thing namely that the implementing machinery has not been doing well. We are prepared to say that there are certain things that are required to be done. I do not think everything is perfect in our machinery. Improvemnt should be made in it. As a matter of fact, many of the amendments which are before us to-day will go further in strengthening the machinery and in plugging many of the loopholes therein. To a very great extent improvement is made in the working of the R B.I. Some of the Members originally had wanted that there should be a full debate on it, it should be under Parliament's scrutiny and there should be examination of the working of the R.B.I. I think that more or less has turned out to be a debate on the working of the R.B.I. All matters whether it is the Cooperative sector, or the nationalised bank's sector or big people or small people, finance or re-finance, agriculture, or industry, almost all these things, have come under the gamut of discussion to-day. Moreover, last year this matter came up before the consultative Committee. Last year, on the 20th February or so, there was a full debate on the working of the R B.I. There were also questions regarding various aspects of the R.B.I.

There are certain basic amendments. First of all I would like to take this very simple amendment of extending the refinancing facility for apex cooperative banks for subsidiary activities undertaken not jointly but independently of agriculture. They were not taken jointly but also they were taken exclusively which included sheep-breeding too, as mentioned by the hon. Member, the other day. By and large, these would be welcomed by all the Members here.

My second amendment is for providing finances for the development of fisheries and by providing agricultural credit. I think that also has been welcomed by almost all Members About the collection of information, even now there is a provision for collecting the information. For this, paper approval of RBI has to be undertaken. Moreover, a certain statutory protection is also necessary to financial institutions and that has been created by this amendment. Moreover the definition of the credit information has also been enlarged. It is not only regarding the quantity but is also regarding the security given by the borrowers and the guarantee by the institutions in the background of credit worthiness, antecedents and capacity of the persons or the borrowers in this country This is according to the recommendations of the Banking Commission regarding widening the sphere or the method of the credit information. That will be a healthy thing. I think that though there may be one or two solitary voices, on the whole, this has been welcomed by all the Members.

श्री जनेश्वर मिश्र: : आप प्राइम मिनिस्टर से अच्छा बोलती हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या कहते हैं, आप ? आप, मैं और प्राइम मिनिस्टर तीनों इलाहाबाद के हैं, पवित्र संगम से आते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं ?

श्री मधु लिमये : यह तो आप के लिये कम्पलीमेन्ट है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कोई भाई तारीफ़ करे तो अच्छा लगता है, लेकिन किस मंशा से आप ऐसा कह रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : मंशा तो अच्छा है आप की तारीफ़ कर रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मधु जी, आप का नाम बड़ा मधुर है, अगर मधुर भाषा में बोलें तो अच्छा है।

श्री मधु लिमये : इसी लिये तो कह रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: *Madhu* means honey. It is the bee's stings that are very painful but the honey is sweet.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I am in no position to say whether this was relevant or not.

About the fourth amendment, that is about the non-banking institution, Prof. Dandavate has gone too far as compared to the provisions provided for by the R.B.I. The definition of "deposits" of the non-banking institutions has been made more comprehensive and precise. It also provides the R.B.I. the power to inspect the non-banking institutions.

That is a provision which, I think, has been wanting for a very long time. Moreover, this will make it obligatory not only for the companies but also for the brokers to disclose all the particulars and information before they canvas for deposits. This is something which will be welcomed in the interest of financial discipline and for seeing to it that the interests of the depositors are also safeguarded.

These are the main amendments and on the basis of these amendments we have seen the entire gamut of the discussion, how they have shifted and how again they came back to them.

Before I go into two or three controversial points raised earlier, I would like to take up some other points. One was about credit policy. Here within the financial constraints and within the resources at our disposal—recently there was also a meeting to consider this—we have found that it is extremely difficult in present circumstances to get all the things moving. So naturally we have to choose priorities. Priorities are what they ought to be; there can be no two views about it. The first priority is agriculure. Then we have the distributing machinery, also the wage goods, core industries and exports. I do not think people can disagree on these. According to the priority, what ever money is there has been distributed. This is the credit policy which has been evolved after much thinking and working by the RBI. When the credit policy is attacked on the ground that this industry is suffering or that industry is suffering, or the larger one is suffering or the smaller one is suffering, this is the norm that is followed; is it necessary in the interest of the country at present, how far it can be financed, whether not financing it would be detrimental to the larger interest of the consumers of the consumer goods which are required by the people at large?

An hon. member raised the point about chit funds. This is a State subject. Many State Governments have their own laws about it. The Banking Commission had suggested that the RBI draw up a uniform Bill which should eventually be adopted by all States. In the meantime, the States have been advised to copy from some other States where they are already operating their laws. Meanwhile, the RBI is in the process of preparing a model Bill.

The hundi business came up for discussion, and rightly too. This is one of those things on which a recommendation was made by the Banking Commission, that this indigenous banking agency should eventually go. As a policy, Government have taken a decision to this effect. After nationalisation and the new approach, we find that all the additional finance which is being made available to all these agencies, the multanis and others, should really stay at the existing level. They should be frozen at this level, gradually they should be declining and within the course of two years they should be stopped. The RBI is working

in that direction. Certain steps are being studied as to how soon this should be effected. Advice has been given to all the banks last year. We are already working in that direction and I think it should, by and large, be welcome.

Another point was about the continuity of the directors. I do not know why every step taken by Government seems to stir up some sort of suspicion somewhere. This is a very innocuous simple thing. Even in regard to the nationalised banks, when due to some reason or other, a new director is not being appointed or it was not possible to appoint him, in order to see that there is no vacuum or gap, the present incumbent continues for that time.

श्री मधु लिमये : क्या चार साल में नया एप्वाइन्टमेन्ट नही हो सकता । क्या चार साल में नये डायरैक्टर के बारे में तय नही कर सकते हैं ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: This is also the same pattern as is followed by the nationalised banks.

SHRI MADHU LIMAYE: Wrong pattern.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: There is nothing really to conjure up suspicion, of ghosts, in the motives of Government

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): In enternity, four years are nothing.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Then as regards deposits received by non-banking companies about which Shri Madhu Limaye wanted information, I have tried to collect as information as possible. But I am not in a position to say that we have all the information. But the information we have tried to collect will, I think, satisfy even a member of his curiosity and information.

I think that the non-banking companies can accept deposits from the public up to 25 per cent of their paid-up capital and net reserves. He specifically asked me about the percentage of it. I am told—and this is to the best of our information—that Maruti does not exceed this in any manner.

SHRI MADHU LIMAYE: It is wrong; I will prove it.

मैं 115 आप के खिलाफ़ नही दूंगा । मैं क्लाजेज और तीसरे बाचन पर बोलूगा ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: He should be happy with the information that I have supplied to him in a short time

Now, then second point is this. The Banking Commission had made certain recommendations on this and on the basis of that, it has been decided that the existing legal provisions in the Reserve Bank and the directions also, regarding the deposit activities of the non-banking companies should be tightened and the loopholes plugged. A Study Group has also been appointed under the Chairmanship of Shri James Raj, Chairman of the Unit Trust of India to go into all the aspects, examine them in detail and examine the suggestions, vecause this is one thing which the Government wants to do. How it has to be done and how quickly it will be done will depend on the study made and the report of the Study Group which is going into it

I would like to say that under the directions issued by the Reserve Bank for exercising control over the deposit activities of non-banking companies, a non-banking company can raise deposits from the public up to an extent of 25 per cent of the aggregate of the paid-up capital and the net free reserves.

SHRI MADHU LIMAYE: And minus the losses.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Term "deposit", as per the Reserve Bank's directions, does not however

[Shrimati Sushila Rohatgi]

apply to money received by the company from purchasing and selling and other agents or any advance received by the company against orders for goods, properties or services. The Reserve Bank directions do not, therefor, apply to the deposits collected by a company from the distributors as a trade practice, and such deposits raised by companies for purchasing, selling or distributing agencies have been outside the purview of the Reserve Bank's directions right from the beginning, that is, right from the year 1966 when the Reserve Bank issued these directions for the first time.

A point was raised by an hon. Member from Kerala and that was about the coir industry. I am happy to say that approval has been given to the coir industry by the RBI and that is included as an industry for refinance. But the details are being worked out: the Planning Commission has set up a task force which is going into all the details as to how it is going to be worked out. But the RBI's approval has already been given regarding the coir industry in Kerala.

Then, an hon. Member has mentioned about workers' participation. He said that there should be workers' participation on the Board of Directors. All I have to say is that this RBI is a policy-making body. When we had workers' representatives on the nationalised banks, that was in the new context of a new clientele; there was a new context of taking the banking facilities to the neglected sector, to the rural areas. Therefore, it was considered necessary and rightly too, that the participation of workers would go a long way in bringing about better working conditions there. So, by and large, we found that this has been a very successful experiment also. But in this particular case, this is a policy-making body where people with a certain economic background, people having mature experience and knowledge of credit policy and economic matters, are required; that is absolutely necessary. As to how far workers' representatives will be able to assist here, assist in the deliberations of the policy-making body, as a Central bank, is a different matter. So, the hon. Member who raised the point would realise that here the question does not seem to have the same importance.

With these few words,—I hope I have covered all the points that have been raised by hon. Members—I would commend to hon. Members that they should approve of this and I hope they would give it their unanimous support.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up clause-by-clause consideration. From clause 2 to clause 24, there are no amendments whatsoever.

SHRI MADHU LIMAYE: I want to speak on clause 17.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, let me put up to clause 16.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 16 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up clause 17.

Clause 17—(Amendment of section 451)

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि रिजर्व बैंक के वर्तमान निदेशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक डिपाजिट्स लिये जा सकते है। 25 प्रतिशत काहे का ? यह बुनियादी सवाल इस मे है। रिजर्व बैंक के जो डायरेक्शन मेरे पास आये हैं उस में चूंकि नान-बैंकिंग, नान-फ़ाइनेंशियल कम्पनी है मारुति लिमिटेड, उस के बारे मे बोल रहा हू। इन्हो ने मारुति लिमिटेड के बारे में कहा कि किसी तरह की इर्रेगुलैरिटी नही हुई अब मै साबित कर रहा हूं रिजर्व बैंक के जो निर्देश हैं उन का कबम कदम पर मारुति लिमिटेड ने उल्लंघन किया रिजर्व बैंक का यह डायरेक्शन देखिये, जैसा सुशीला जी ने अभी कहा :

"In the case of any other deposit 25 per cent of the aggregate of the paid up capital and free reserves of the company".

इस में मतभेद नही है। लेकिन मै उन का ध्यान पेज 7 पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस की ओर खींचना चाहता हू। यह सफेद कागज है, नीला कागज तो फ़ाइनेंशियल कम्पनीज के बारे में है। तो पेज 7 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है :

"Page 5, Explanation: In arriving at the aggregate of the paid up capital and the free reserves for the purpose of sub paragraph of para 3(2) there shall be deducted from the aggregate of the paid up capital as appearing in the balance sheet of the company account of accumulated balance and loss if any disclosed in the balance sheet."

25 परसेंट काहे का ? पेड अप कपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्युमुलेटड लासेज़। अगर वित्त मंत्री जी इस बात को काटना चाहती है तो मैं बैठ जाता हूं ; और अगर नही काटती हैं तो मैं आगे बढ़ता हू। मैं मारुति का लास्ट बैलेंस शीट लाया हूं। अगर आप देखना चाहती है तो देख सकती है। इस में पेड अप कैपिटल दिखाई गई है मैं राउन्ड फ़िगर्स ले रहा हूं, 1 करोड 54 लाख, और रिजर्व दिखाये गये हैं 6 लाख 80 हजार। तो टोटल हो जाता है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ 61 लाख। अब इस में लासेज दिखाये गये है मारुति बैलेंस शीट के 11 पेज पर एक्युमुलेटड लासेज दिखाये गये है 58 लाख। तो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्वज माइनस लासेज जो बैलेंसशीट मे डिसक्लोज किये गये है उस के अनुसार 58 लाख अगर कम किया जायगा तो पेड अमाउन्ट आयेगा 1 करोड़ 2 लाख। इस का 25 प्रतिशत क्या होगा ? 25 लाख 40 हजार। डिपाजिट्स कितने है ? इन के पेज 8 पर दिखाये गये है 28 लाख और 2 लाख 50 हजार। मैं डायरेक्टर्ज की गारन्टी वाला डिपाजिट छोड़ रहा हूं, गारटी बिना वाला डिपाजिट ही पकड़ रहा हूं। 28 लाख और अढाई लाख यह तीस लाख हो जाता है।

अब मैं मारुति बैलेंस शीट के पेज 18 की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। इस मे आडिटर्ज के नोट्स हैं। आडिट नोट नम्बर 1 मे कहा गया है :

Auditor's notes: 1. Share application money Rs. 46,41,000.

आगे आडिटर्ज के कमेंट है .

The aforesaid amount of Rs. 46,41,000 includes sums aggregating Rs. 20,43,000 received by the company upto 31st March, 1974 in respect of which formal applications have yet to be received from the applicants concerned.

17 hrs.

[श्री मधु लिमये]

यह शेयर कैपिटल नहीं है। 46 लाख रुपया क्या है? शेयर कैपिटल के तौर पर मिला है। 26 लाख के लिए कम से कम एप्लीकेशंज हैं, एैलाटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बीस लाख रुपया मारुति लिमिटड में जमा है जिस के लिए फार्मल शेयर एप्लीकशन्ज नहीं है। यह तो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। यह डिपाजिट नहीं है तो क्या है? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मारुति लिमिटेड के पास बीस लाख की जो रकम जमा है जिसके बारे में शेयर एप्लीकेशन भी नहीं है और मेरी राय के अनुसार यह ब्लैक मार्किट का पैसा है जिस के लिए फार्मल शेयर एप्लीकेशंज भी नहीं हैं लेकिन यह कम्पनी के पास है तो इसको तो डिपाजिट्स में ही पकड़ना चाहिए। इन तीनों को यदि पकड़ा जाएगा तो यह कुल मिला कर 51 लाख हो जाता है। ये ले सकते हैं पच्चीस लाख। लेकिन 51 लाख डिपाजिटस के रुप में जमा है। चूंकि प्रधान मंत्री का लड़का मैनेजिंग डायरेक्टर है इसलिए आप बिना सोचे समझे न कुछ कह दें। में प्रेम पूर्वक कहना चाहत हूं कि जब हम लोग बात करते हैं तो उस में बहुत सोचने समझने की कोशिश करते हैं हालांकि आपके रिजर्व बैंक ने मुझ से कोआप्रेट नहीं किया है इस में लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने साबित किया है कि डिपाजिट की जो लिमिट रिजर्व बैंक के निर्देशों के साथ रखी गई थी यह 25 परसेंट की थी और इन्होंने 50 परसेंट स अधिक डिपाजिट लिया है। इसमें मैं डीलर्ज डिपाजिट नहीं पकड़ रहा हूं। अब मैं उस पर आ रहा हूं।

डीलर्ज डिपाजिट क्या है। कमर्शियल ट्रांजैकशंज के लिए जो डिपाजिट लिए जाते हैं वे 25 परसेंट की लिमिट में नहीं आते हैं लेकिन अब हम लोगों को यह एग्जैमिन करना है कि 2 करोड़ 18 लाख के डीलर्ज डिपाजिट पेज 10 पर दिखाई गए हैं मारुति बैलेंस शीट के ये क्या हैं। यह बैलेंस शीट इनके पास जरूर आया होगा। आप पूछेंगे क्यों आया होगा? तो एक नियम में आपको पढ़ कर सुनाता हूं रिजर्व बैंक का। इनको सब इनफर्मेशन देनी पड़ती है रिजर्व बैंक को।

Returns to be made to the Reserve Bank: Without prejudice to the provisions of para 11, every non-banking, non-financial company, which holds deposits as on 31st March, in any year shall submit to the Reserve Bank a return furnishing the information specified in the first schedule with reference to its position as on 31st March and every non-banking, non-financial company carrying on or financing hire-purchase transactions shall furnish a return...." etc.

आप स्पष्ट उत्तर दें कि क्या मारुति लिमिटेड ने अपने रिजर्व बैंक के पास डिपाजिट के बारे में पूरी तरह फाइल किए हैं। क्यों मैं यह सवाल उठा रहा हूं? इस वास्ते कि रिजर्व बैंक ने अपने डायरेकशन में कहा है कि उनके डायरेक्शन का हौंगज यह मतलब नहीं है कि डिपाजिट्स के डिपाजिट्स हर हालत में प्रोटेक्ट हो जायेंगे। उसके निदेशों का यदि उल्लंघन होता है तभी वह कार्रवाही कर सकता है। लेकिन मैंने साबित किया है कि रिजर्व बैंक के डायरेकशंज का मारुति लिमिटेड ने उल्लंघन किया है और रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई कर सकता है?

"The Reserve Bank has powers to prosecute institutions and or persons for their failure, if any, to comply with the directions issued by it."

लेकिन जो रिजर्व बैंक का गर्वनर सरकार की इजाजत के बिना ज्वायंट पार्लिमैंटरी कमेटी के सामने एवीडेंस देते वक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार न हो उस डरपोक आदमी से म आशा नहीं करता हूं कि प्रधान

मंत्री के लड़के की कम्पनी के खिलाफ वह किसी तरह की कार्रवाई करेगा। आज इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इकोनोमिक आफेंसिस की जब बात चलती है तो जो बड़े लोगों के बेटे या बच्चे हैं उनको हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। मिर्धा साहब से मैं कहना चाहता हूं कि 1968 में उप प्रधान मंत्री के बेटे का जब सवाल उठा था तब आप में से कई लोगों ने मेरा उस समय साथ दिया था लेकिन उप-प्रधान मंत्री से भी बड़े प्रधान मंत्री के लड़के की जब बात करता हूं तो आप लोग चुप्पी साधते हैं।

डीलर्ज डिपाजिट का जहां तक सवाल है उस में उन्होंने 2 करोड़ 18 लाख इकट्ठा किया है। रिजर्व बैंक की जो अभी उन्होंने परिभाषा पढ़ी उस में उसकी व्याख्या की गई है। सुशीला जो ने अभी कहा कि ट्रेडिंग परपजिस के लिए परचेजिंग एजंट्स या सैलिंग एजंट्स जो इकट्ठा किया जाता है वह उसमें नहीं आएगा। लेकिन डिपाजिट जो सैलिंग ऐजट से या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जाते हैं वह तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और उस कमर्शियल ट्रांजैक्शन में किसी भी एजेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर को यह जरूर आशा रही होगी कि कम से कम उसको नेट दस परसेंट रिटर्ज मिले। मैं जानना चाहता हूं कि मारुति ने कौन सी प्रोडक्ट्स उनको बेचीं, कौन सी प्रोडक्ट बेचेगा, ऐसी उम्मीद थी जबकि प्रोटोटाइम तक टैस्ट नहीं हुआ था, इण्डस्ट्रियल लाइसेंस तक नहीं मिला था दो साल से ये डिपाजिट लिए जा रहे हैं।

Is it a non commercial transaction? Is this contribution being made on the basis of non-commercial considerations?

अगर नान कमर्शियल है तो मैं कहूंगा कि डिपाजिट की व्याख्या में इसका भी उल्लेख होना चाहिए। यह बोनाफाइड नहीं है। अगर थोड़ा भी निष्पक्ष ढंग से इस पर सोचेंगे तो मारूति प्रोडक्ट ही नहीं आया। उसकी इतनी गाड़ियां मझे मिलेगी इस तरह की आशा एजंट को नहीं। प्रोटोटाइम टैस्ट नहीं हुआ था और इंडस्ट्रियल लाइसेंस तो 31 मार्च के बाद ही आप लोगों ने दिया है। ये बोनाफाइड डीलर्ज डिपाजिट्स नहीं है। इसको भी मैं इस में सम्मिलित करना चाहिए, डिपाजिट्स में करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि पचास लाख और ये दो करोड़ अठारह लाख, कुल मिलाकर दो करोड़ 68 लाख हो जाते हैं और पेड अप कैपिटल वगैरह एक करोड़ का होता है। मतलब यह हुआ कि तकरीबन अढाई गुना" से भी अधिक कैपिटल। तो यह कम्पनी कोई बोनाफाइड ढंग से चल न रही है। मेरा निवेदन है कि इस कम्पनी के एक एक शेयरहोल्डर के बारे में आप जांच करें। चौदह महीने से मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे है। इन में से एक मेरा आदमी है जो विदाउट फायर आफ कंट्रेडिक न में कह सकता हूं कि इकोनोमिक आफेंडर है। दो तो स्मगलर है। ये लोग हमें सिखाते हैं? मेरी बातों का आप अभी जवाब दें नहीं तो थर्ड रीडिंग पर मुझे फिर बोलना पड़ेगा और मामले को सदन के सामने रखना पड़ेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot repeat your argument.

SHRI MADHU LIMAYE: I am not repeating. I am bringing fresh material and fresh arguments. I will continue to do it until I ferret out the truth.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Continuing what my hon. friend has said, I want to know whether an overdraft has been given to the Prime Minister's son by the Central Bank of India and, if so, what are the details. Because, the Reserve Bank is supposed to exercise control

[Shri Jyotirmoy Bosu]

over every banking operation. I would like the hon. Minister to explain the relationship between this company and Drilling Equipment Private Limited, Maruthi (Technical Services) Private Limited and so many others a socialist mother and a big capitalist son!

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये जी ने जो आर्ग्यूमेंट" पिछले शुक्रवार को उठाए थे उस के आधार पर जितनी अधिक से अधिक रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त की जा सकती थी वह प्राप्त करने की कोशिश हम ने की और वह में आप के सामने रखना चाहती हूं। मुझे यह बताया गया है कि मारुति किसी प्रकार से भी रिजर्व बैंक के किसी भी आदेश या निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है। आप की राय हो सकती है... (व्यवधान).....

The word "Maruti" may or may not provoke. That is a different matter. But since Shri Madhu Limaye has raised certain points today, I shall certainly look into them from that angle. So far as my information goes, I have been told positively that the Maruti has not, in any way, contravened any direction of the R.B.I. But still because he has raised it, we will ask the R.B.I. to look into it. After that, no explanation is required.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Limaye, you raised certain specific points. She says that she will ask the Reserve Bank to look into them She is not in a position to reply to the points now.

SHRI MADHU LIMAYE: You promise to make a statement?

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI: One point more. I would beg of the hon. Member how far it is correct in parliamentary practice to call any person, may be the Governor of the Reserve Bank, a *darpok* when he is not in a position to justify himself. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. I do not exactly follow the exact meaning of the word "*darpok*".

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI: It means "coward". (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Cowards die many times before death. I hope, Mr. Madhu Limaye will die only once. The question is:

"That Clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17 *was added to the Bill.*

Clauses 18 *to* 24 *were added to the Bill.*

Clause 25—(*Insertion of new section* 58*A.*)

SHRI M. C. DAGA: I beg to move:

Page 11,—

omit lines 13 to 17. (3)

मैं संविधान की धाराओं की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप स्टेट और इंडिविजुअल में फर्क क्यों समझते है? आप इस में कहते है :

"No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the Bank for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done...."

That means, if any damage is caused to any property, you debar a suit being filed against the Bank. If I want to go to the court and say that they have caused damage to my property, I cannot do it; I am debarred from going to the court.

तो फिर तो मना कर दें कि रेलवे के अंदर भी कोई सूट फाइल नहीं करना चाहिए। मैंने 1934 के बाद यह कोट किया कि इतने केसेज हुए जिस में हर्जाना हुआ। तो आप यह अमेंडमेंट लाना क्यो चाहते है? आप चाहते हैं कोई न्याय के लिये कोर्टस में न जाय? गुड फेथ की जांच कौन करेगा। मैं एक वकील के नाते यह जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have the hang over from the morning. I know of night hang over but not of morning hang-over.

SHRI M. C. DAGA: Article 16 says:

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment..."

So far as law is concerned, all should have the equal opportunity to file a suit.

आप उसको ईक्वल अपा चुनिटी क्यों नही देना चाहते? और आप यह बताइये कि यह अमेडमेट आप ला क्यों रहे है?

आप को क्या दिक्कत पेश हुई, क्या आवश्यकता पड़ी जिस के लिए आप यह अमेंडमेट ला रहे है?

Why are you bringing this amendment? How many cases have been instituted against the Bank? Why are you bringing this legislation? Is there any judgment against you?

तो मेरी कुछ समझ में नही आता कि यह अमेडमेंट आप क्यों लाए? इसलिए मैंने यह अमेडमेंट रखा है कि आप मेहरबानी करके इसे डिलीड कर दीजिए। आप कोर्ट को डिवार मत कीजिए, अदरवाइज आप के बैंकों के एम्प्लाईज जो हैं व ज्यादा नैग्लीजेंस और केयरलेसनैस करेंगे और उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी मैं ने पहले भी डागा जी को काफी समझाने का प्रयास किया था। लगता है वह सारा विफल गया है। शायद वह समझना नही चाहते या मैं समझा नहीं पाती। मैं यही कहना चाहती हूं कि जो सही काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं उनकी गुड फेथ के साथ में कुछ प्रोटेक्शन दिया जाय यही इसकी मंशा है। और नेशनेलाइज्ड बैंकों में भी यह चीज शामिल है और उसी के आधार पर सिमिलर चीज इस मे प्रोवाइड की गई है। इस में हम कोई और चीज नही करने वाले है .....(व्यवधान)

मै आग्रह करूगी कि वे इस चीज को ज्यादा प्रैस न करें। मैं गुड फेथ नही उन की गुड विल को अब अपील करूंगी कि इस को अब प्रेस न करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you pressing your amendment, Mr. Daga?

SHRI M. C. DAGA: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will put it to the House. Mr. Daga is in the class of Oliver Goldsmith's school teacher, "For even though vanquished, he could argue still".

I now put the Amendment moved by Shri Daga to Clause 25 to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 25 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 25 was added to the Bill.

Clause 26—(Insertion of new section 58B, 58C, 58D, 58E and 58F.)

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I move:

Page 13, lines 12 and 13,—

for "no court inferior to that of a presidency magistrate or a magistrate of the first class".

substitute—

"no court other than that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class or a court superior thereto". (1)

Page 13, line 15,—

for "1898" *substitute* "1973". (2)

SHRI M. C. DAGA: I move:

Page 11, line 32,—

after "person" *insert* "wilfully". (4)

SHRI M. C. DAGA: I have moved my amendment. Suppose I have some documents and I have lost them in the train. I go to the Bank and say, 'I have lost the documents' and you say 'No'. The amendments you are bringing, kindly me make me understand. After all what are we doing? If a man is to produce some documents, please give him a chance. Tell me that I am wilfully or deliberately avoiding to produce the documents.

जब एक दफा ला कमीशन ने इकानामिक आफेन्सेज के बारे में यह माना है कि बर्डन एक्यूज्ड पर डाल दिया जाय—

The burden lies on the accused to prove.

तो फिर आप यह कहना चाहते हैं— I have failed to produce. Then you say, 'you are debarred.'

आप दो हजार का जुर्माना कर देंगे, सजा दे देंगे ।

I have simply said that if any person wilfully fails to produce or conceals the documents, them you can punish him.

आप क्यों इकोनामिक आफेंस में इस तरह से पनिशमेन्ट देना चाहते है, इस में आप को क्या नुकसान है ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have already explained the position. I think it should satisfy him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the question is:

Page 13, lines 12 and 13,—

for "no court inferior to that of a presidency magistrate or a magistrate of the first class"

substitute—

"no court other than that of a metropolitan magistrate of a judicial magistrate of the first class or a court superior thereto" (1)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:

Page 13, line 15.—

for "1898" *substitute* "1973". (2)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I will put amendment No. 4 of Shri Daga to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, मै दो तीन बातो के सम्बन्ध मे आप की मारफत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हू। इन्हो ने रिजर्व बैंक की कर्ज की नीति की बात कही है और सरकार के अनुसार इन की कर्ज की नीति जनता के हक म है, इस से जनता को फायदा हो रहा है, वह जनता चाहे किसान हो, मजदूर हो या उद्योगधधों मे काम करने वाले लोग हों। लेकिन उपाध्यक्ष जी, मेरा अनुभव कुछ दूसरा है। इन की जो कर्ज की नीति है वह बुनियादी तौर से देश के अन्दर इजारेदार पूजीपतियों की मजबूत करने वाली है। यह मै इस लिये कह रहा हू कि आज जितना भी कर्ज राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस का 70–75 फीसदी बडे घरानो के पास, पूजीपतियों और सरमायेदारों के पास जा रहा है। किसानो को अनाज पैदा करने के लिये, खेती के दूसरे सामानों के लिये, बेकार ग्रेजुएटस या जो छोटे किसान है या छोटे छोटे उद्योगधधों मे काम करने वाले लोग है यदि आप ध्यान से देखे तो बहुत ही कम हिस्सा कर्ज का इन लोगों को मिल पाता है। यद्यपि सरकार कहती है कि हम इन को कर्ज देना चाहते है, समाज मे इन्हे स्थापित करना चाहते है, इन को अपने पाव पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इन की कर्ज की नीति ठीक इस के विपरीत है और अभी तक इस कर्ज नीति का ज्यादा से ज्यादा भाग धन्ना सेठो को या धन कुबेरो को जा रहा है।

यदि यह बात नही है तो मैं सरकार से निवेदन करूगा कि राष्ट्रीयकृत बैंको या रिजर्व बैंक के कामो के बारे मे जाच का अधिकार पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी को दे दीजिये–आप को मालूम हो जायेगा। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी ने बार बार इस बात की माग की है कि जैसे हम दूसरे सरकारी कारखानों की खराबियो और अच्छाइयो की जाच करते है, उसी तरह से बैंकों के बारे मे भी जाच करने का अधिकार पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी को होना चाहिये। लेकिन मुझे मालूम है, सरकार अभी तक इस के लिये तैयार नही हुई है और पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के पत्रो का यह जवाब दिया गया है कि सरकार इसे उचित नही समझती। मै पूछता हू क्यो उचित नही समझती, क्या बात है ? आज तमाम कारखानो की जाच का अधिकार आप पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी को दे सकते है, लेकिन जहा हिन्दुस्तान की जनता के धन का सवाल है, उसको इस के परख्यू से क्यों अलग रखना चाहते है ? इससे लोगो के मन म सन्देह होना स्वाभाविक है क्योंकि उस की जो कर्ज देने की नीति है, जो गडबडी, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, उस मे है, उस का आप साफ नही होने देना चाहते। अगर ऐसी बात नही है तो मै कहूंगा कि आप बैंको को पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के जाच करने के अधिकार म दे दीजिये।

दूसरी बात–अभी इन्हों ने एक बात कही-जिस से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मे नही लिया जायेगा, क्योंकि वे क्रेडिट पालिसी को समझ नही सकते। मैं समझता हू कि यह कर्मचारियों का उपहास करना है, मजदूर वर्ग इन अपमानजनक शब्दों को बरदाश्त नही करेगा

[श्री रामावतार शास्त्री]

उन डायरेक्टर्स को इसलिये लिया जाता है क्योंकि वे बड़े घरानों से आते हैं, कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आते हैं, इस वजह से वे बड़े निपुण हो गये हैं और दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि हम समाजवाद बनाना चाहते हैं, जनता का राज बनाना चाहते हैं लेकिन मजदूरों के प्रतिनिधियों को रिजर्व बैंक के बोर्ड में लेने लायक नहीं समझते। मैं ट्रेड यूनियन्ज में काम करता हूं, रिजर्व बैंक की भी किसी यूनियन से मेरा ताल्लुक रहा है। मैं जानता हूं कि आप के डायरेक्टर्स के मुकाबले बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन के लीडर्स उस को ज्यादा समझते हैं। इस तरह की बात आप को नहीं करनी चाहिये थी। यह मजदूरों का अपमान करना है, उनका मजाक उड़ाना है। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्तर पर आप मजदूरों के प्रतिनिधियों को रखिये ताकि आप की कार्यपद्धति ठीक से चले और जो उसकी कर्ज देने की नीति है वह ठीक से चले।

तीसरी बात—यह संशोधन विधेयक रिजर्व बैंक के बारे में है। आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाइज एसोसियेशन की कान्फ्रेंस पिछले अप्रैल में हुई थी, उन्होंने उसमें एक चार्टर आफ़ डिमाण्ड्स आप को दिया था, लेकिन आप उस पर बैठी हुई हैं। अगर आप की सरकार उनका कीआपरेशन नहीं लेगी तो क्या बैंकों को काम ठीक से चलेगा। उन की एफिसियन्सी को बनाय रखने के लिये जरूरी है कि आप उन की बातों पर ध्यान दें। उनकी उस आल इण्डिया कान्फ्रेंस में जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि उनके चार्टर आफ़ डिमाण्ड्स पर जल्दी फैसला कीजिये ताकि उनका असन्तोष दूर हो सके। पटना में रिजर्व बैंक की शाखा है, बहुत दिनों तक मैं वहां की यूनियन का प्रेसीडेंट था। वहा पर हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट्स के बहुत लोग काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंटल प्रोमोशन रोकों से रुका हुआ है। मेरा ख्याल है भारत में सभी जगह ऐसा होता। डिपार्टमेंटल प्रोमोशन देने में आपके अधिकारी अगर मगर क्यों कर रहे हैं? आप यहां कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने का उन का मौका आता है तो सरकार उन के साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करती है। यह कहां का न्याय है इस जनतांत्रिक पद्धति में इसलिये मेरा कहना है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को डिपार्टमेंटल प्रोमोशन दीजिये और उन के असन्तोष को दूर कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Mr. Bosu, I am intrigued to find the paper which he has sent that he wants to speak on Delhi Sales-Tax Bill; he wants to speak on Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill; he wants to speak on the Indian Telegraph (Amendment) Bill; then, of course, he wants to speak on R.B.I. (Amendment) Bill which is relevant here. Also he wants to speak on the Bill which I cannot read. On which Bill do you wart to speak?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On Reserve Bank of India (Amendment) Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have written in anticipation of the Bills to be taken up in this session.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You are quite right.

Sir, a very alarming thing has come out. The net return of the nationalised banks in this country has gone down alarmingly. The Reserve Bank is supposed to be a body which is entrusted by a statute to supervise the functioning of the banks in the country. When the banks were nationalised, it became more of an important duty for the Reserve

Bank to see that the nationalised banks functioned properly.

I would place before you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when speaking on one of the motices, that they have utterly failed. In an earlier discussion, that was raised by me, I said that the Reserve Bank had totally and utterly failed in fulfilling any of its duties.

Sir, one of the malpractices that has come to light and which has been adopted by the foreign banks particularly, by the National and Grindlays Bank is that in one year, its income is to the extent of nearly about a crore of rupees. The bank has been charged with remitting the money out of this country which is far above what they should have done under all these statutes, rules and regulations.

We see the Reserve Bank adopting a pious look and remaining as a passive spectator. This white elephant does not deserve the ration that the country is providing to such institutions

Now a very recent thing is that the Indian rupee's value in the international market has gone down by 10 per cent. I want to know from the hon. Minister whether they are preparing for a devaluation? My suspicion is that after Mr. Kissinger's visit here and a revelation of 10 per cent reduction in Indian rupees value in the foreign market is only a preamble to the step which will ultimately be devaluation of the Indian rupee. Of course, the induction of Mr. Subramaniam is also another indication that devaluation is coming! He is a specialist in devaluation.

I do not understand why this Reserve Bank could be outside the audit purview of the Comptroller and Auditor General of India. I also want to know why it has not been allowed to be scrutinised by a Parliamentary Committee. What is there that you want to hide in the Reserve Bank? It is consuming a huge amount of money. It has not given any account of itself. That is quite evident from the deteriorating economic conditions in this country.

I do not wish to say much but another recent thing which is alarming and which really demands an immediate probe is the revelation that certain officials of the RBI were involved in a big foreign exchange racket. We would have liked Government to tell us all about it instead of hiding these stinking skeletons in their cupboard. They are very good at that.

Lastly, I would support the charter of demands that had been given by the RBI employees. As usual; on the one hand the Government allow the foreign bankers to loot this country and on the other they allow the officials to run a beautiful racket to fill their kitty, but when the small employees come before them with a reasonable demand which would mean only their survival by meeting the minimum requirements of human living, Shrimati Rohatgi with all the good appearances that she wears in the House has no time to fulfil those minimum obligations. I condemn this action. I condemn this Government for allowing the RB to do nothing but at the same time consume the limited resources that we have and that too in big quantities I do not approve this. I only hope that Government will do, as any right-thinking sort of people should, with regard to the Reserve Bank of India.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Shri Jyotirmoy Bosu with all his eloquence forget to mention one thing and that was the class character of the party. Otherwise all the issues he raised were already raised before.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I did not catch the first sentence.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I was congratulating him on his

[Shrimati Sushila Rohatgi]

fertile imagination about devaluation and other things, but was saying that among the other allegations he made he forget to mention the normal allegation about the class character of the Congress Party.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order. Shrimati Rohatgi came into the Government not too long ago. I also admit that I was not a member of this House when devaluation was clamped on this country in 1966. But I know that the agenda for the Cabinet when devaluation got its clearance was partitioning of Punjab, and the Cabinet Ministers who were dragged to the meeting after disturbing their afternoon nap did not know what they were talking about Yet the rupee was devalued after that.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K RAGHU RAMAIAH). Is the disclosure of what all happened in the Cabinet not a violation of the Official Secrets Act?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you accept that that is a secret.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मान्यवर, मैं रामावतार शास्त्री जी की बड़ी इज्जत करती हूं। वह आम तौर पर बड़ी गम्भीरता के साथ भाषण देते हैं। आज पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी बात गलत समझी, मुझे इस का दुख है यदि उन्होंने सोचा है कि वर्कर्स को रिजर्व बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर न लेने की मैंने राय दी और किसी प्रकार से मैं ने उन पर आघात किया है, या उन की क्षमता पर हमें विश्वास भी नहीं है। कभी भी मेरे मन में यह भावना नहीं थी। बकस का जहां तक अनुभव है वह हम जानते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उन को लिया गया है और मैं ने कहा कि उन के आने से हमारी कार्यशैली अच्छी हुई है और दृष्टिकोण भी बदला मिला। लेकिन जहां तक रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स का मामला था उस में इकोनामिक ऐस्टीमेटस और मानीटरी स्टेबिलिटी के ऊपर ऐक्सपर्ट लोग चाहियें। कुछ साल पहले जो हमारे डायरेक्टर्स थे उस में ज्यादातर इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग थे। अब आप देखेंगे तो उस में इकोनोमिस्टस, ऐग्रीकल्चरिस्ट, लायर्स और जूरिस्ट हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: और ऐडवाइजरी कमेटी में बड़े-बड़े इकोनोमिस्ट प्रोफेसर्स भी हैं। एशियन कैबिल्स का कोहन्का लोग बैठे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मेरा शास्त्री जी से कहना है कि अगर उन के मन में यह भावना आयी कि वर्कर्स की क्षमता पर हमें शक है तो यह गलत है। अगर वर्कर्स के मन में इस तरह की भावना है तो उस के हमारी बैंक की कार्यशैली पर प्रभाव पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं चाहती हूं। सेंट्रल बोर्ड पर एक बार वर्कर्ज का रिप्रिजेंटिव लेने का प्रयास हुआ था लेकिन उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आप त्यागपत्र दे दो और उनको छोड़ कर हट जाना पड़ा था। यह एक्स पेरिमेंट किया गया है। वह एक ऊंचे स्तर के आदमी थे। उनको हटना पड़ा था। आज सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्ज में इस कारण से वर्कर्ज का रिप्रिजेंटिव नहीं है।

कर्जों का भी उन्होंने जिक्र किया है। यह ठीक है कि कुछ कर्जा ऐसे लोगों को पहुंच गया है जिन को नहीं पहुंचना चाहिये था। यह भी ठीक है कि जो ज्यादा जरूरतमन्द हैं उनको बड़ी दिक्कतें है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जो इसके बारे में एक बिल है वह दोनों हाउसिज की सिलेक्ट कमेटी के सामने है और वहीं इस पर सोच-विचार हो रहा है। वह जब यहां आएगी तो उस पर और विचार किया जाएगा। तब आपको और बातें कहने का मौका मिल जाएगा।

मेरा विश्वास कि इन सब बातों को देखते हुए मास्त्रीजी इसका स्वागत करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों या सहकारी समितियों के माध्यम से जो कर्जा दिया जाता है हो सकता है कि उस में थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को चला जाता हो जहां नहीं जाना चाहिये। लेकिन छोटे लोगों की कास्तकारी की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय ग्रुप बनाया था फार्मर्ज सर्विस सोसाइटी के रूप में जो केवल ऋण ही नहीं और भी जितनी चीजें है, कंसलटैंसी सर्विस है, मार्किटिंग है, रा मैटेरियल है, इन सब के बारे में बताए कि किस तरह सहकारी समितियों, राष्ट्रीयकृत बैंका आदि के माध्यम से इन सारी चीजों का सामजस्य करके ज्यादा ज्यादा ऋण उनके पास पहुंच सकते हैं जिन को ऋणों की ज्यादा जरूरत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

17.43 hrs.

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER This Bill is a simple one. The Government wants to legalise the levy of a small fee for application forms

SHRI DINESH JOARDER (Malda): Sir, a point of order In the list of business, against item 9, it is seen that Shri Jagganath Pahadia is to move the motion for consideration of the Bill Has the Minister of Communications taken permission to move the motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER. It is all right; he has taken. Even so, Minister means any Minister, according to the rules.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR SHANKAR DAYAL SHARMA): I move:

"That the Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Sir, as you have mentioned, it is a very simple Bill. This is an amendment to section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 This is just to legalise the levy of Rs. 10 with the application which was put through under rule 414, but later on the Committee on Supbordinate Legislation suggested that it will be better if we amend the Act for providing this levy, that is, charging Rs 10 on the form. So, the amendment has been brought

The Bill has only three clauses one is for the title of the Bill The second one deals with the amendment to section 7. The third one is only about legalising the recovery of this Rs 10 per form from 1st December 1969, to the passing of the Bill

As was said by the hon. Deputy Speaker, it is a very simple Bill and I hope the House will pass it

17.44 hrs.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair*].

MR CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI DINESH JOARDER (Malda) I oppose this Bill. Though the Chair termed it is a simple Bill, this is not a simple Bill It is going to legalise an illegal act committed by the P&T administration in 1969 in charging a fee of Rs. 10 termed an error. This error was a motivated and calculated error. The Indian Telegraphs Act was passed in 1885 and since then it was being applied. There was no chance of committing any error. It was known to the officers and the Ministry people also; they knew